

बीईई लाईन

अंक-31, अप्रैल-जून, 2026

त्रैमासिक समाचार पत्रिका

ई - कुकिंग
विशेषांक





इलेक्ट्रिक कुकिंग : आपके परिवार के लिए स्मार्ट विकल्प ⚡

- कम समय में खाना बनाएं
- सुरक्षित रसोई - न गैस लीक, न आग का खतरा
- स्वच्छ हवा - कोई प्रदूषण नहीं
- ऊर्जा के साथ साथ पैसे की बचत

ई कुकिंग अपनाएं
स्वच्छ हवा और बचत दोनों पायें





विषय सूची

पृष्ठ संख्या

संदेश

महानिदेशक महोदय का संदेश	04
सचिव बीईई महोदय का संदेश	05

ई-कुकिंग विशेष

भारत में ई-कुकिंग	06
भारतीय खाना पकाने की नई सोच	09
ई-कुकिंग से जुड़े प्रमुख तथ्य	11

मुख्य समाचार झलकियाँ (अप्रैल, 2026)

जम्मू में आयोजित एनसीईईआईटीईटी 2026 में ऊर्जा दक्षता पहलों का प्रदर्शन	13
राज्यों में ईसीएसबीसी के कार्यान्वयन पर राज्य पीएमयू की समीक्षा बैठक	13
बीईई-ISA सहयोग से ऊर्जा डेटा तंत्र होगा सुदृढ़	14
कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लिए MRV पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम	14

मुख्य समाचार झलकियाँ (मई, 2026)

स्वच्छता पखवाड़ा 2026 : जागरूकता एवं जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छता का संदेश	15
ऊर्जा दक्ष मोटर्स और उन्नत इंडक्शन कुकिंग प्रौद्योगिकियों पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श	16
एडीटी (ADEETIE) के अंतर्गत वित्त तक पहुँच सुदृढ़ करने पर आयोजित कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी	16
रायपुर में स्टील री-रोलिंग क्लस्टर हेतु ADEETIE कार्यशाला	17
आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों की ऊर्जा मांग संबंधी रिपोर्ट जारी	17
कानपुर लेदर क्लस्टर के लिए ADEETIE हितधारक संवाद कार्यशाला	18

मुख्य समाचार झलकियाँ (जून, 2026)

ब्लिक्स साइड इवेंट के रूप में 'विद्युत उपकरणों के मानकों को उन्नत बनाने' विषय पर आयोजित कार्यक्रम	19
बीईई ने ऊर्जा-कुशल भवनों और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए तमिलनाडु के साथ सहयोग सुदृढ़ किया	20
अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आयोजित योग सत्र	20
ईसीएसबीसी मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम का आयोजन	21
समाचारों की सुर्खियों में ई-कुकिंग	22



संपादकीय बोर्ड



संपादकीय बोर्ड के अध्यक्ष
महानिदेशक, BEE



मुख्य संपादक:
सचिव



संपादक
मीडिया प्रबंधक



अस्वीकरण:

अस्वीकरण: सर्वाधिकार सुरक्षित। इस पुस्तक के सभी नियति अधिकार पूर्णतः ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी (BEE) के पास सुरक्षित हैं। इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को पुनः प्रस्तुत, किसी पुनर्प्राप्ति प्रणाली में संग्रहीत या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से - इलेक्ट्रॉनिक, यांत्रिक, फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग या अन्य माध्यमों द्वारा प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना प्रकाशित नहीं किया जा सकता है।

सामग्री के अनधिकृत उपयोग पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।



महानिदेशक ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का संदेश

अप्रैल-जून 2026 की अवधि के दौरान ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने तथा देश में एक सुदृढ़ ऊर्जा दक्षता पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण पहल की हैं। इस अवधि में ईसीएसबीसी (ECSBC) मास्टर ट्रेन्सर्स के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों के साथ समीक्षा बैठकें संपन्न हुईं, ऊर्जा दक्ष प्रौद्योगिकियों पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श किया गया तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSMEs) को ऊर्जा दक्ष समाधान अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु ADEETIE योजना के अंतर्गत कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

ब्यूरो ने भारतीय सांख्यिकी संस्थान (Indian Statistical Institute) के सहयोग से भारत के ऊर्जा डेटा तंत्र को सुदृढ़ बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। साथ ही, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (Carbon Credit Trading Scheme) के प्रभावी क्रियान्वयन की तैयारी को मजबूत करने के उद्देश्य से विशेष मापन, प्रतिवेदन एवं सत्यापन (MRV) प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये पहल साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को सशक्त बनाएंगी तथा भारत की उभरती जलवायु एवं ऊर्जा संबंधी प्राथमिकताओं को गति प्रदान करेंगी।

राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर हमारी सक्रिय भागीदारी, जिसमें विद्युत उपकरणों के मानकों को उन्नत करने पर आयोजित ब्रिक्स (BRICS) साइड इवेंट भी शामिल है, ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक नेतृत्वकारी भूमिका तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग के प्रति

हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वहीं, स्वच्छता पखवाड़ा, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस तथा विभिन्न इंजीनियरिंग प्रदर्शनियों में सहभागिता जैसी जन-जागरूकता गतिविधियों के माध्यम से सतत जीवनशैली एवं ऊर्जा दक्ष व्यवहार के प्रति व्यापक जनभागीदारी को प्रोत्साहन मिला है।

आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों की ऊर्जा मांग पर व्यापक रिपोर्टों का सफलतापूर्वक प्रकाशन, राज्यों को ईसीएसबीसी (ECSBC) तथा ईएनएस (ENS) के प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर सहयोग तथा उद्योग, शिक्षण एवं तकनीकी संस्थानों, वित्तीय संस्थाओं और राज्य सरकारों के साथ सुदृढ़ होती साझेदारियाँ ऊर्जा दक्षता के लिए एक मजबूत एवं समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने की हमारी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करती हैं।

ये सभी उपलब्धियाँ विद्युत मंत्रालय, राज्य नामित एजेंसियों, उद्योग जगत, तकनीकी संस्थानों, विकास सहयोगी संगठनों तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निरंतर सहयोग, समर्पण और प्रतिबद्धता का परिणाम हैं। मैं, सभी हितधारकों के प्रति उनके अमूल्य सहयोग एवं निरंतर समर्थन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

आगे भी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नवाचार को बढ़ावा देने, कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने तथा सामूहिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा, ताकि ऊर्जा दक्ष, सतत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के राष्ट्रीय संकल्प को साकार किया जा सके।



सचिव

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का संदेश

विगत तिमाही (अप्रैल-जून, 2026) के दौरान बीईई के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण पहल की गई। हालांकि, बीईई लाइन का यह अंक विशेष रूप से ऐसे विषय पर केंद्रित है, जो हमारे रोजमर्रा के जीवन से जुड़ा है- “ई-कुकिंग”।

खाना पकाना हर भारतीय घर का अभिन्न हिस्सा है। जैसे-जैसे हमारी ऊर्जा व्यवस्था विकसित हो रही है, वैसे-वैसे खाना पकाने के हमारे तरीके भी अधिक स्वच्छ, सुरक्षित और ऊर्जा-दक्ष हो सकते हैं। इंडक्शन कुकटॉप और अन्य ऊर्जा-दक्ष विद्युत उपकरण अधिक सुविधा और दक्षता प्रदान करते हैं तथा रसोई के भीतर ईंधन के दहन से होने वाले उत्सर्जन से बचने में मदद करते हैं। भारत की विद्युत व्यवस्था जैसे-जैसे अधिक स्वच्छ और हरित हो रही है, ई-कुकिंग भी स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा के हमारे व्यापक लक्ष्यों में योगदान दे सकती है।

ई-कुकिंग को अपनाने के लिए एकाएक बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को एक अतिरिक्त, ऊर्जा-दक्ष और व्यावहारिक विकल्प उपलब्ध कराना है। किफायती उपकरण, विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति, भारतीय भोजन पकाने के अनुरूप तकनीक और उपभोक्ताओं में जागरूकता-ये सभी ई-कुकिंग को व्यापक रूप से अपनाने के लिए महत्वपूर्ण होंगे।

बीईई के लिए यह ऊर्जा दक्षता को लोगों के रोजमर्रा के जीवन के और करीब लाने का भी एक अवसर है। जिस

प्रकार ऊर्जा-दक्ष प्रकाश व्यवस्था ने लाखों भारतीय घरों में ऊर्जा दक्षता को पहुँचाया है, उसी प्रकार ऊर्जा-दक्ष खाना पकाना भी घरेलू स्तर पर सार्थक बदलाव का एक महत्वपूर्ण अवसर बन सकता है।

इस तिमाही के दौरान बीईई ने सतत भवनों, एमएसएमई में ऊर्जा दक्षता, कार्बन बाजार, ऊर्जा संबंधी डेटा, उपकरणों की ऊर्जा दक्षता और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्रों में भी अपना कार्य जारी रखा है। ये प्रयास बड़े पैमाने पर ऊर्जा बचत हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी, नीतियों, साझेदारियों और व्यवहार में बदलाव को साथ लेकर चलने के हमारे व्यापक दृष्टिकोण को दर्शाते हैं।

अंततः ऊर्जा दक्षता केवल बड़े उद्योगों और भवनों तक सीमित नहीं है। यह हमारे घरों में हर दिन किए जाने वाले विकल्पों से भी जुड़ी है। रसोई में किया गया एक छोटा बदलाव, जब लाखों परिवारों द्वारा अपनाया जाता है, तो वह भारत के लिए एक बड़े बदलाव में योगदान दे सकता है।

मुझे आशा है कि बीईई-लाइन का यह विशेष अंक हमारे पाठकों को खाना पकाने के अधिक स्वच्छ, स्मार्ट और ऊर्जा-दक्ष तरीकों की संभावनाओं को जानने के लिए प्रोत्साहित करेगा।



भारत में ई-कुकिंग

क्या बिजली भारतीय रसोईघर को बदल सकती है?

क्या हो, अगर भारत में खाना पकाने का भविष्य किसी और गैस सिलेंडर से नहीं, बल्कि एक बिजली के सॉकेट से आए ?

भारत स्वच्छ ऊर्जा प्रणालियों की ओर आगे बढ़ रहा है, ऐसे में इलेक्ट्रिक कुकिंग, या "ई-कुकिंग", स्वस्थ घरों, अधिक ऊर्जा सुरक्षा और एक अधिक सतत भविष्य के लिए एक आशाजनक समाधान के रूप में उभर रही है।

कुकिंग महत्वपूर्ण विषय क्यों है?

खाना पकाना भारतीय घरों की सबसे अधिक ऊर्जा-गहन गतिविधियों में से एक है। हालांकि भारत ने स्वच्छ कुकिंग ईंधन तक पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, किफायती और सतत कुकिंग ऊर्जा सुनिश्चित करना अभी भी एक चुनौती बना हुआ है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)¹ के अंतर्गत, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की महिलाओं को 10 करोड़ से अधिक LPG कनेक्शन वितरित किए जा चुके हैं, जिससे लाखों लोगों को पारंपरिक बायोमास ईंधनों से दूर होने में मदद मिली है। फिर भी, रिफिल की बढ़ती कीमत के कारण कई परिवार LPG के साथ-साथ लकड़ी, फसल अवशेष और उपले का उपयोग जारी रखे हुए हैं।

इसने वैकल्पिक स्वच्छ कुकिंग विकल्पों, विशेषकर इलेक्ट्रिक कुकिंग में रुचि को नए सिरे से जगाया है।

ई-कुकिंग क्या है?

ई-कुकिंग का अर्थ है, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में बिजली का उपयोग करके भोजन तैयार करना। इसमें निम्नलिखित उपकरण शामिल हैं:

- ♦ इंडक्शन कुकटॉप्स
- ♦ इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर
- ♦ राइस कुकर
- ♦ माइक्रोवेव ओवन
- ♦ इन्फ्रारेड स्टोव
- ♦ इलेक्ट्रिक केतली



1. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय। (2026)। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY)। भारत सरकार। (PMUY).

2. विश्व स्वास्थ्य संगठन। (2025)। घरेलू वायु प्रदूषण और संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव। WHO। यह प्रकाशन अनुमान लगाता है कि 2019 में वैश्विक स्तर पर घरेलू वायु प्रदूषण के संपर्क में आने से लगभग 3.2 मिलियन मौतें हुईं (विश्व स्वास्थ्य संगठन).

♦ मल्टी-फंक्शनल स्मार्ट कुकर

पारंपरिक ईंधनों के विपरीत, ई-कुकिंग में रसोई के अंदर दहन शामिल नहीं होता, जिससे यह एक स्वच्छ और स्वस्थ विकल्प बन जाता है।

एक स्वस्थ रसोईघर

क्या आप जानते हैं कि पारंपरिक कुकिंग ईंधनों से निकलने वाला धुआं एक बहुत बड़ा लोक स्वास्थ्य चिंता बना हुआ है?

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)² के अनुसार, घरेलू वायु प्रदूषण श्वसन संबंधी बीमारियों और हृदय रोगों में महत्वपूर्ण योगदान देता है। महिलाएं और बच्चे विशेष रूप से इससे प्रभावित होते हैं क्योंकि वे कुकिंग स्थानों के पास अधिक समय बिताते हैं।

इलेक्ट्रिक कुकिंग उपयोग के स्थान पर धुएं का उत्पादन समाप्त कर देती है, जिससे फाइन पार्टिकुलेट मैटर और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक प्रदूषकों के संपर्क में आना कम हो जाता है। एक धुआं-मुक्त रसोई का अर्थ है स्वच्छ दीवारें, स्वस्थ परिवार और बेहतर जीवन गुणवत्ता।



दक्षता मायने रखती है

ई-कुकिंग के प्रमुख लाभों में से एक अधिक ऊर्जा दक्षता की इसकी संभावना है।

इंडक्शन कुकिंग पारंपरिक गैस कुकिंग से अलग तरीके से कार्य करती है। लौ उत्पन्न करके बर्नर से कुकिंग बर्तन तक ऊष्मा स्थानांतरित करने के बजाय, इंडक्शन प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा का उपयोग करके सम्बंधित बर्तनों को सीधे गर्म करती है। इससे आसपास के परिवेश में नष्ट होने वाली ऊष्मा की मात्रा कम हो जाती है, और यह रसोई को अधिक ठंडा रखने में भी मदद कर सकता है।

यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी³ के अनुसार, इंडक्शन उपकरण गैस स्टोव की तुलना में तीन गुना तक अधिक ऊर्जा-कुशल हो सकते हैं और पारंपरिक स्मूथ-टॉप इलेक्ट्रिक रेंज की तुलना में 10 प्रतिशत तक अधिक कुशल हो सकते हैं। बेहतर ऊर्जा दक्षता के अतिरिक्त, इंडक्शन कुकटॉप्स बर्तनों को तेजी से गर्म कर सकते हैं और सटीक तापमान नियंत्रण प्रदान करते हैं।

इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर उन खाद्य पदार्थों के लिए भी दक्षता लाभ प्रदान कर सकते हैं जिन्हें लंबे समय तक पकाने की आवश्यकता होती है, जैसे चावल, दाल, बीन्स और भारतीय घरों में आमतौर पर उपभोग किए जाने वाले अन्य मुख्य खाद्य पदार्थ। इलेक्ट्रिक हीटिंग को प्रेशर कुकिंग के साथ मिलाकर ये उपकरण कुकिंग समय को कम कर सकते हैं और अनावश्यक ऊष्मा हानि को न्यूनतम कर सकते हैं।

भारतीय घरों के लिए, जहां खाना पकाना एक दैनिक और ऊर्जा-गहन गतिविधि है, कुशल इलेक्ट्रिक कुकिंग प्रौद्योगिकियों को व्यापक रूप से अपनाने से अधिक सुविधा और एक स्वच्छ कुकिंग वातावरण प्रदान करते हुए ऊर्जा खपत में कमी लाने में योगदान मिल सकता है।

3. यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी (2023)। इंडक्शन स्टोव या कुकटॉप्स की ओर परिवर्तन करना। ऑफिस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी एंड रिन्यूएबल एनर्जी, यू.एस. डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी।

4. विद्युत मंत्रालय। (2026)। सौभाग्य: प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना। भारत सरकार। सरकारी आंकड़ों के अनुसार सौभाग्य अवधि के दौरान 2.86 करोड़ घरों का विद्युतीकरण किया गया।



भारत में बिजली लाभ

सौभाग्य योजना⁵ जैसी पहलों के माध्यम से भारत ने लगभग सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण हासिल कर लिया है, जिससे ई-कुकिंग का तेजी से उपयोग किया जा रहा है।

साथ ही, देश तेजी से अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का विस्तार कर रहा है। भारत ने सौर, पवन, जल और परमाणु ऊर्जा सहित गैर-जीवाश्म ईंधन स्थापित क्षमता में 200 GW का आंकड़ा पार कर लिया है।

जैसे-जैसे विद्युत ग्रिड अधिक हरित होता जाता है, बिजली से खाना पकाना भी उतना ही स्वच्छ होता जाता है।

नवीकरणीय बिजली का उपयोग करके तैयार किया गया हर भोजन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में योगदान देता है और 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने की भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करता है।

ऊर्जा सुरक्षा लाभ

भारत अपनी LPG आवश्यकताओं का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है, जिससे घरेलू कुकिंग वैश्विक ईंधन कीमतों में उतार-चढ़ाव से प्रभावित होती रहती है।

इलेक्ट्रिक कुकिंग घरेलू ऊर्जा स्रोतों में विविधता लाने और आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम करने का अवसर प्रदान करती है।

जैसे-जैसे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ता है, ई-कुकिंग घरेलू ऊर्जा उत्पादन का समर्थन करते हुए भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ कर सकती है।

आगे की चुनौतियां

अपने लाभों के बावजूद, ई-कुकिंग को अभी भी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

कुछ क्षेत्रों में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति एक चिंता बनी हुई है। शुरुआती उपकरण लागत भी कम आय वाले परिवारों को हतोत्साहित कर सकती है। एक इंडक्शन स्टोव की कीमत ₹2,000 से ₹4,000 के बीच हो सकती है, जबकि इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर की कीमत ₹3,000 से ₹8,000 तक हो सकती है।

सांस्कृतिक प्राथमिकताएं भी एक भूमिका निभाती हैं। कई परिवार मानते हैं कि रोटी या पारंपरिक व्यंजन खुली आंच पर पकाने पर बेहतर स्वाद देते हैं।

इसलिए विशेषज्ञ एक क्रमिक परिवर्तन का सुझाव देते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक कुकिंग मौजूदा LPG उपयोग को पूरी तरह बदलने के बजाय उसका पूरक बने।

आगे की राह

क्या भारत अपनी LED लाइटिंग क्रांति के समान एक इलेक्ट्रिक कुकिंग क्रांति का अनुभव कर सकता है?

संभावनाएं उत्साहजनक हैं। घटती उपकरण कीमतें, बिजली अवसंरचना में सुधार, बढ़ता नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, और तकनीकी नवाचार ई-कुकिंग को अधिक सुलभ बना रहे हैं।

ऊर्जा-कुशल उपकरणों के लिए प्रोत्साहन, कुकिंग के लिए किफायती बिजली टैरिफ, और जागरूकता अभियान जैसे नीतिगत उपाय इसे अपनाने में तेजी ला सकते हैं।

अंततः, ई-कुकिंग केवल कुकिंग उपकरण बदलने के बारे में नहीं है। यह स्वस्थ घर बनाने, पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने, महिलाओं को सशक्त बनाने, और एक अधिक सतत ऊर्जा भविष्य के निर्माण के बारे में है।

कल की रसोई न केवल अधिक स्मार्ट और स्वच्छ हो सकती है, वे बिजली से भी संचालित हो सकती हैं, जिससे हर भोजन भारत के व्यापक स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन में एक छोटा योगदान बन जाए।

5. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। (2026)। नवीकरणीय ऊर्जा उपलब्धियां। भारत सरकार। मंत्रालय के अनुसार, भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर-जीवाश्म स्रोतों का हिस्सा 53.7% है। (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)



भारतीय खाना पकाने की नई सोच:

ई-कुकिंग की ओर एक ऊर्जा-कुशल परिवर्तन

जैसे-जैसे परिवार अपनी ऊर्जा पसंद पर पुनर्विचार कर रहे हैं, इंडक्शन कुकिंग गैस के मुकाबले एक स्वच्छ, अधिक स्मार्ट विकल्प के रूप में उभर रही है।



पीढ़ियों से, गैस की फुसफुसाहट और लाइट की क्लिक भारतीय रसोई में भोजन की शुरुआत का संकेत देने वाली परिचित नीली लौ को प्रज्वलित करती आई है। कुछ ही समय पहले तक, भारतीय खाना पकाना पूरी तरह लकड़ी, कोयला, या उपले जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर था। लेकिन 1955 में एक बदलाव आया, जब बर्मा-शेल ने वाणिज्यिक रूप से लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस (LPG) पेश की; और एक दशक बाद, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOCL) के इंडेन के माध्यम से, इसे व्यापक रूप से जनता तक पहुंचाया गया। पाइंड नेचुरल गैस (PNG) जल्द ही 1970 के दशक में एक स्वच्छ और अधिक सुविधाजनक शहरी विकल्प के रूप में इसका अनुसरण करती नज़र आई। दोनों तब से हमारे दैनिक जीवन में इतने रच-बस गए हैं कि हममें से अधिकांश शायद ही कभी इन पर सवाल उठाते रहे हैं। लेकिन हाल के वर्षों ने उस सवाल को अपरिहार्य बना दिया है।

अस्थिर ऊर्जा बाजारों और आपूर्ति व्यवधानों से पाया गया है कि जीवाश्म-ईंधन निर्भरता कितनी असुरक्षित हो सकती है। जब भी LPG की कमी या कीमतों में वृद्धि हुई है, यह सवाल उठता है: शायद केवल ईंधन को नहीं, बल्कि हमारे खाना पकाने के तरीके पर नए सिरे से सोचने की जरूरत है।

इलेक्ट्रिक कुकिंग, या ई-कुकिंग, इसका एक व्यावहारिक जवाब है और उपलब्ध विकल्पों में, इंडक्शन हॉब आज उपलब्ध सबसे कुशल और आसानी से सुलभ प्रौद्योगिकियों में से एक के रूप में सामने आते हैं।

परिवर्तन क्यों करें?

हालांकि भारत ने LPG पहुंच बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, उच्च लागत, डिलीवरी में अंतराल, और ईंधन स्टैकिंग के कारण निरंतर उपयोग अभी भी एक चुनौती बना हुआ है और जहां LPG प्रमुख कुकिंग ईंधन है, वहां भी यह स्वास्थ्य लागतों से मुक्त नहीं है। गैस स्टोव सीधे रसोई और आसपास के स्थानों में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (NO₂), कार्बन मोनोऑक्साइड (CO), और फाइन पार्टिकुलेट मैटर (PM_{2.5}) छोड़ते हैं। इन प्रदूषकों के लंबे समय तक संपर्क को श्वसन रोगों, हृदय संबंधी समस्याओं, और कुछ कैंसर के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है। महिलाएं और बच्चे, जो अक्सर रसोई के पास अधिक समय बिताते हैं, विशेष रूप से प्रभावित होते हैं। पहले से गर्म हो रहे वातावरण में, इंडोर गर्मी और प्रदूषकों के एक अतिरिक्त स्रोत को समाप्त करना पहले से कहीं अधिक मायने रखता है। यह इंडक्शन कुकिंग का एक स्पष्ट लाभ है। यह दहन को पूरी तरह समाप्त कर देता है, जिससे कोई धुआं या इंडोर उत्सर्जन नहीं होता। परिणाम एक स्वच्छ, स्वस्थ रसोई है।

दक्षता एक अन्य क्षेत्र है जहां इंडक्शन का स्पष्ट लाभ है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) रेखांकित करती है कि आधुनिक इंडक्शन हॉब अपनी खपत की गई ऊर्जा का 90% तक उपयोग योग्य ऊष्मा में परिवर्तित कर सकते हैं, जिसे वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के माध्यम से सीधे बर्तन तक स्थानांतरित करते हैं। इसकी तुलना में, गैस स्टोव आसपास की हवा में ऊष्मा की एक बड़ी मात्रा खो देते हैं। ऊर्जा उपयोग के प्रति सचेत परिवारों के लिए, यह अंतर समय के साथ जुड़ जाता है, जो कम ऊर्जा खपत और कम उपयोगिता लागत में तब्दील होता है।

अभी यह बदलाव करने का एक बड़ा, संरचनात्मक लाभ भी है। भारत का विद्युत ग्रिड तेजी से रूपांतरण से गुजर रहा है। देश की कुल स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता मार्च 2025 में 220 GW को पार कर गई, जिसमें

1. कर; अभिषेक; सुनील मणि; आद्या शर्मा; सूर्य शेखर औड़ी; श्रुति शर्मा; परस भट्टराई; राहुल दास (2024)। भारत की स्वच्छ कुकिंग ईंधन आपूर्ति में सुधार: लास्ट-माइल एलपीजी उपलब्धता बढ़ाने हेतु सिफारिशें। नई दिल्ली: काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर (CEEW)।
2. एकाधिक लेखक (2024)। अमेरिकी स्टोवों में गैस और प्रोपेन दहन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के संपर्क में आना, स्वास्थ्य प्रभाव, और उससे जुड़ी जनसांख्यिकीय असमानताएं। साइंस एडवांसेज।



अकेले सौर ऊर्जा का हिस्सा 105 GW से अधिक है — जो 2014 के बाद से 2,500% से अधिक की वृद्धि है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में एक रिकॉर्ड 29.52 GW नवीकरणीय क्षमता जोड़ी, और सरकार ने अपनी पंचामृत प्रतिबद्धताओं के तहत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।

2024 में ₹75,021 करोड़ के परिव्यय के साथ शुरु की गई पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना जैसी योजनाओं का लक्ष्य वित्त वर्ष 2026-27 तक एक करोड़ परिवारों में रूफटॉप सोलर सिस्टम स्थापित करना है, जिससे स्वच्छ बिजली उत्पादन सीधे घरों में पहुंचेगा। “जैसे-जैसे अधिक नवीकरणीय ऊर्जा ग्रिड में जुड़ती है, बिजली स्वयं क्रमशः अधिक हरित ईंधन बनती जाती है। आज खरीदा गया एक इंडक्शन हॉब उपयोगकर्ता से किसी भी बदलाव की आवश्यकता के बिना, कल के उस स्वच्छ ग्रिड से स्वतः लाभान्वित होगा। इस अर्थ में, ई-कुकिंग केवल वर्तमान के लिए नहीं, बल्कि भविष्य के लिए भी एक निवेश है।

भारतीय रसोईघर के लिए बनी एक प्रौद्योगिकी

इंडक्शन कुकिंग को लेकर सबसे आम चिंताओं में से एक यह है कि क्या यह भारतीय व्यंजनों और उनके विविध स्वाद प्रोफाइल के साथ न्याय कर सकती है। इसका तुरन्त जवाब हां है।

दाल तड़का को लें, जिसे तेज आंच चाहिए, या बिरयानी को, जिसे धीमी आंच पर दम चाहिए जिसमें धैर्य और तापमान पर सटीक नियंत्रण आवश्यक है। आधुनिक इंडक्शन हॉब दोनों को सटीकता के साथ संभालते हैं, ऐसा तापमान नियंत्रण प्रदान करते हुए जिसका गैस की लपटें जो उतार-चढ़ाव और असमान ऊष्मा वितरण के अधीन होती हैं अक्सर मुकाबला नहीं कर पातीं। इंडक्शन हॉब गैस स्टोव की तुलना में अधिक तेजी से गर्म होते हैं, जिससे कुल कुकिंग समय भी कम हो जाता है।

अधिकांश इंडक्शन हॉब फ्लैट-बॉटम स्टील और कास्ट-आयरन बर्तनों के साथ जुड़े होते हैं, इस प्रकार के बर्तन जो पहले से ही अधिकांश भारतीय रसोई घर में पाए जाते हैं। उनकी चिकनी सतह को पारंपरिक बर्नर ग्रेट्स की तुलना में साफ करना आसान होता है, और चूंकि कुकटॉप स्वयं अत्यधिक गर्म नहीं होता, गैस स्टोव की तुलना में आकस्मिक जलने का जोखिम भी काफी कम होता है। छोटे बच्चों वाले परिवारों के लिए, यह एक महत्वपूर्ण सुरक्षा लाभ है।

वाणिज्यिक रसोई और खाद्य व्यवसाय भी ई-कुकिंग की ओर परिवर्तन से लाभान्वित हो सकते हैं। विश्वसनीय ऊष्मा उत्पादन, कम अग्नि जोखिम, और कम वेंटिलेशन आवश्यकताएं इंडक्शन को न केवल एक पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ विकल्प बनाती हैं, बल्कि एक परिचालनात्मक रूप से कुशल विकल्प भी बनाती हैं।

भारत कहां खड़ा है और यह कहां जा सकता है

भारत अपने ऊर्जा परिवर्तन रोडमैप के एक महत्वपूर्ण चरण में है। घरों, उपकरणों और दैनिक विकल्पों के माध्यम से मांग-पक्ष पर ऊर्जा दक्षता में सुधार करना ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने जितना ही महत्वपूर्ण है। ई-कुकिंग स्वाभाविक रूप से इस दृष्टिकोण में फिट बैठती है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो इंडक्शन हॉब को अपने मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रम के अंतर्गत लाने की दिशा में कार्य कर रहा है, जो उपभोक्ताओं को उपकरण चुनते समय सुसूचित, ऊर्जा-कुशल निर्णय लेने में मदद करेगा।

बेशक, इस परिवर्तन को रातों-रात होने की आवश्यकता नहीं है। कई परिवार बैकअप के रूप में एक गैस कनेक्शन रखते हुए, अपने दैनिक खाना पकाने को यथासंभव इंडक्शन हॉब की ओर स्थानांतरित कर रहे हैं; इस प्रकार व्यवहार में परिवर्तन लाते हुए ई-कुकिंग की ओर परिवर्तन को सुगम बना रहे हैं।

एक छोटा परिवर्तन, एक बड़ा प्रभाव

हमने पहले भी लकड़ी या उपले से गैस स्टोव में अपने खाना पकाने के तरीके को अनुकूलित किया है। गैस स्टोव को इंडक्शन हॉब से बदलना शुरुआत में कठिन लग सकता है, उस लौ की कमी के कारण जिसके हम इतने आदी हैं; फिर भी यह छोटा घरेलू निर्णय एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। लाखों घरों, रेस्तरां और वाणिज्यिक रसोईघरों को जोड़ा जाए, तो यह छोटा निर्णय आयातित जीवाश्म ईंधनों पर कम निर्भरता, भारत के लिए अधिक ऊर्जा सुरक्षा, और एक स्वच्छ व अधिक कुशल भविष्य की ओर एक सार्थक कदम का अर्थ रख सकता है।

वह लौ जिसने पीढ़ियों से भारतीय खाना पकाने को परिभाषित किया है, हमारी अच्छी सेवा करती आई है। लेकिन भारतीय रसोई का अगला अध्याय उतना ही समृद्ध और स्वादिष्ट हो सकता है, साथ ही स्वच्छ, सुरक्षित और अधिक कुशल भी।

ई-कुकिंग की ओर परिवर्तन करें।

स्वच्छ पकाएं। स्मार्ट पकाएं। कुशलता से पकाएं।

शबरीन रायसा रहमान

स्वतंत्र सलाहकार, आईसीएफ कंसल्टिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

3. वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता ने हासिल की ऐतिहासिक वृद्धि। प्रेस सूचना ब्यूरो।

4. पीएम सूर्य घर: भारत की सौर क्रांति। प्रेस सूचना ब्यूरो।

अस्वीकरण: इस लेख में व्यक्त विचार एवं मत पूर्णतः लेखक के निजी हैं। इन्हें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), विद्युत मंत्रालय अथवा भारत सरकार के आधिकारिक विचार, नीतियाँ या आधिकारिक दृष्टिकोण को नहीं दर्शाते।

ई-कुकिंग से जुड़े प्रमुख तथ्य स्वच्छ स्मार्ट हरित

सबसे स्वच्छ खाना पकाने की तकनीकों में से एक

- 1 ई-कुकिंग में खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल (केरोसीन) या एलपीजी जैसे ईंधनों को जलाने के बजाय बिजली का उपयोग किया जाता है।
- 2 चूंकि उपयोग के स्थान पर किसी प्रकार का दहन नहीं होता, इसलिए ई-कुकिंग से रसोईघर में धुआँ नहीं होता और घरेलू स्तर पर प्रत्यक्ष उत्सर्जन भी नहीं होता, जिससे घर के भीतर की वायु गुणवत्ता बेहतर होती है।

ई-कुकिंग भारत के ऊर्जा परिवर्तन को गति देती है

- 1 जैसे-जैसे भारत का विद्युत ग्रिड सौर और पवन ऊर्जा के बढ़ते उपयोग से अधिक स्वच्छ बन रहा है, वैसे-वैसे बिजली से खाना पकाना भी कम कार्बन उत्सर्जन वाला विकल्प बनता जा रहा है।
- 2 खाना पकाने जैसे अंतिम उपयोगों का विद्युतीकरण (Electrification) नेट ज़ीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने की महत्वपूर्ण रणनीतियों में से एक माना जाता है।

आयातित ईंधनों पर निर्भरता कम करने में सहायक

- 1 देश में नवीकरणीय ऊर्जा से उत्पादित बिजली के बढ़ते उपयोग से आयातित एलपीजी और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता कम होती है, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और मजबूत होती है।

भारत में ई-कुकिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है

- 1 ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) की "गो इलेक्ट्रिक" पहल के अंतर्गत ई-कुकिंग तकनीकों को ऊर्जा दक्ष और स्वच्छ विकल्प के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है।

आधुनिक ई-कुकिंग केवल
इंडक्शन तक सीमित नहीं है

ई-कुकिंग कई सतत विकास
लक्ष्यों (SDGs) को समर्थन देती है

इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर 1

राइस कुकर 2

मल्टी-कुकर 3

माइक्रोवेव ओवन 4

इलेक्ट्रिक केटल 5

एयर फ्रायर 6

इन्फ्रारेड कुकटॉप 7



1 SDG 3: अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण

2 SDG 5: लैंगिक समानता

3 SDG 7: सस्ती एवं स्वच्छ ऊर्जा

4 SDG 11: टिकाऊ शहर एवं समुदाय

5 SDG 13: जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी कार्य

भ्रम बनाम तथ्य ई-कुकिंग :

धारणा और वास्तविकता

भ्रम



ई-कुकिंग से खाना धीमा बनता है।



ई-कुकिंग में बहुत अधिक बिजली खर्च होती है।



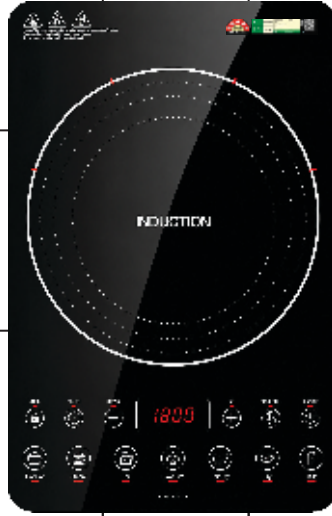
ई-कुकिंग में बने खाने का स्वाद अलग होता है।



ई-कुकिंग सुरक्षित नहीं है।



इलेक्ट्रिक कुकटॉप पर केवल साधारण व्यंजन ही बनाए जा सकते हैं।



तथ्य



आधुनिक इंडक्शन कुकटॉप पारंपरिक गैस चूल्हों की तुलना में 30-50% तक शीघ्र खाना पका सकते हैं, क्योंकि वे न्यूनतम ऊर्जा हानि के साथ सीधे बर्तन को गर्म करते हैं।



इंडक्शन कुकटॉप 85-90% ऊर्जा दक्ष होते हैं, जबकि पारंपरिक गैस चूल्हों की दक्षता केवल 35-55% होती है इसलिए समान भोजन पकाने में अक्सर कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है।



भोजन का स्वाद ताप के स्रोत से नहीं, बल्कि तापमान नियंत्रण, सामग्री और पकाने की विधि से निर्धारित होता है। यही कारण है कि दुनिया भर के कई पेशेवर शेफ इंडक्शन कुकिंग को अपना रहे हैं।



इंडक्शन कुकटॉप में खुली लौ नहीं होती। बर्तन हटाते ही यह स्वतः बंद हो जाता है, जिससे गैस रिसाव और आग लगने का जोखिम काफी कम हो जाता है।



चपाती, रोटी, सब्जी, चावल, दाल, बिरयानी, इडली, डोसा तथा विभिन्न तले हुए व्यंजन सहित अधिकांश भारतीय व्यंजन उपयुक्त इलेक्ट्रिक उपकरणों की सहायता से आसानी से बनाए जा सकते हैं।

क्या आप जानते हैं?



इंडक्शन कुकटॉप में 85-90% ऊर्जा सीधे बर्तन तक पहुँचती है।



इंडक्शन कुकिंग से रोज़मर्रा के कई व्यंजन 50% तक कम समय में तैयार किए जा सकते हैं।



ई-कुकिंग के दौरान रसोई में धुआँ और कालिख नहीं होती।



स्वच्छ रसोई से पूरा परिवार स्वस्थ रहता है, विशेषकर महिलाएँ, बच्चे और बुजुर्ग जो घर के भीतर अधिक समय बिताते हैं।



ई-कुकिंग भारत के ऊर्जा सुरक्षा, स्वच्छ वायु, बेहतर जनस्वास्थ्य तथा वर्ष 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन के राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

मुख्य समाचार झलकियाँ (अप्रैल, 2026)

जम्मू में आयोजित एनसीईईआईटीईटी 2026 में ऊर्जा दक्षता पहलों का प्रदर्शन



जम्मू में आयोजित एनसीईईआईटीईटी 2026 के दौरान जम्मू-कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री श्री उमर अब्दुल्ला बीईई पवेलियन का अवलोकन करते हुए।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने राज्य नामित एजेंसी (SDA), जम्मू व कश्मीर के माध्यम से, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (GCET), जम्मू में आयोजित इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी में उभरते और नवीन रुझानों पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी (NCEEITET) 2026 में भाग लिया।

इस प्रदर्शनी ने ऊर्जा दक्षता, सतत विकास और नवीन ऊर्जा-बचत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने में भारत के प्रयासों को प्रदर्शित करने का एक मंच प्रदान किया। बीईई ने सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को आगे बढ़ाने और

एक सतत ऊर्जा भविष्य के लिए व्यवहार परिवर्तन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अपने प्रमुख कार्यक्रमों और पहलों को रेखांकित किया।

बीईई पवेलियन ने छात्रों, शिक्षाविदों, इंजीनियरों, नीति-निर्माताओं और उद्योग प्रतिनिधियों से महत्वपूर्ण रुचि आकर्षित की। जम्मू-कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री, श्री उमर अब्दुल्ला ने प्रदर्शनी का भ्रमण किया और केंद्र शासित प्रदेश में ऊर्जा दक्षता और सततता को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। अन्य विशिष्ट आगंतुकों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा शिक्षा मंत्री, सुश्री साकिना इट्टू, माननीय एमएलए नगरोटा, सुश्री देवयानी सिंह राणा, तथा बिजली विकास विभाग (PDD), जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री अश्वनी कुमार शामिल थे।

NCEEITET 2026 में बीईई की सहभागिता ने ऊर्जा-कुशल समाधानों को आगे बढ़ाने और भावी इंजीनियरों व नवप्रवर्तकों के बीच जागरूकता बढ़ाने में सरकारी संस्थानों, शैक्षणिक संगठनों और तकनीकी समुदायों के बीच सहयोग के महत्व की पुनः पुष्टि की।

राज्यों में ईसीएसबीसी के कार्यान्वयन पर राज्य पीएमयू की समीक्षा बैठक



बीईई के महानिदेशक ऊर्जा संरक्षण भवन संहिता (ईसीएसबीसी) को सुदृढ़ बनाने हेतु पीएमयू एवं ईसीएसबीसी प्रकोष्ठों की समीक्षा बैठक करते हुए।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने महानिदेशक, बीईई की अध्यक्षता में 15 अप्रैल, 2026 को BEE-GEF-UNDP परियोजना, 'भारत में भवनों में सतत तापीय आराम के लिए अति-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी' के अंतर्गत स्थापित राज्य परियोजना प्रबंधन इकाइयों (PMUs) और ECSBC सेल्स की एक समीक्षा बैठक आयोजित की।

बैठक में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, जम्मू व

कश्मीर, उत्तर प्रदेश, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य नामित एजेंसियों (SDAs) के प्रतिनिधियों के साथ-साथ ECSBC सेल्स का प्रबंधन करने वाली कार्यान्वयन एजेंसियों ने भाग लिया।

चर्चाई ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ECSBC) और इको निवास संहिता (ENS) के अंतर्गत हासिल की गई प्रगति के आकलन पर केंद्रित रही, साथ ही कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाली चुनौतियों की पहचान पर भी। प्रतिभागियों ने फील्ड-स्तरीय क्रियान्वयन को सुदृढ़ करने, हितधारक समन्वय में सुधार करने और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में ऊर्जा-कुशल भवन प्रथाओं को अपनाने में तेजी लाने की आवश्यकता पर बल दिया।

बीईई ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी और संस्थागत सहायता प्रदान करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई तथा देशभर में ECSBC व ENS के प्रभावी और समान कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में समन्वित प्रयासों के महत्व को रेखांकित किया।

बीईई-।S। सहयोग से ऊर्जा डेटा तंत्र होगा सुदृढ़



बीईई एवं भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर

भारत के ऊर्जा डेटा ढांचे को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने मांग-पक्ष ऊर्जा डेटा से संबंधित अनुसंधान, सर्वेक्षण डिजाइन और क्षमता-निर्माण पहलों को बढ़ाने के लिए इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट (ISI), नई दिल्ली के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए।

यह सहयोग सभी क्षेत्रों में ऊर्जा खपत डेटा के संग्रह, विश्लेषण और उपयोग में सुधार करके एनर्जी डेटा मैनेजमेंट यूनिट (EDMU) का समर्थन करने का लक्ष्य रखता है। सांख्यिकीय पद्धतियों और डेटा एनालिटिक्स में ।S। की विशेषज्ञता का लाभ उठाते हुए, यह साझेदारी सुसूचित नीति-निर्माण और प्रभावी कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए गहरी अंतर्दृष्टि उत्पन्न करना चाहती है।

यह पहल विश्लेषणात्मक ढांचों को सुदृढ़ करके, डेटा गुणवत्ता में सुधार करके और साक्ष्य-आधारित निर्णय-निर्माण को सक्षम बनाकर ऊर्जा दक्षता परिदृश्य के भीतर डेटा-आधारित दृष्टिकोणों को बढ़ावा देगी। बेहतर ऊर्जा डेटा प्रणालियों से खपत के रुझानों की बेहतर निगरानी, दक्षता के अवसरों की पहचान और कार्यक्रम परिणामों के मूल्यांकन में सहयोग मिलने की अपेक्षा है।

यह समझौता ज्ञापन एक सुदृढ़ ऊर्जा डेटा तंत्र के निर्माण की दिशा में एक साझा प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करता है, जो भारत के दीर्घकालिक ऊर्जा दक्षता और सततता उद्देश्यों में योगदान देता है।

कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के लिए MRV पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम



नई दिल्ली में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (सीसीटीएस) के लिए आयोजित एमआरवी प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान अधिकारी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने, यूके सरकार के तकनीकी सहायता कार्यक्रम के सहयोग से, 24-25 मार्च, 2026 को नई दिल्ली में कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम (CCTS) के लिए मॉनिटरिंग, रिपोर्टिंग एंड वेरिफिकेशन (MRV) पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

इस कार्यक्रम को CCTS के अंतर्गत MRV प्रणालियों को लागू करने के लिए प्रतिभागियों की समझ और

तैयारी को सुदृढ़ करने हेतु डिजाइन किया गया था। सत्रों में अनुपालन और ऑफसेट तंत्रों दोनों पर लागू निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन प्रक्रियाओं के आवश्यक पहलुओं को शामिल किया गया, जिससे कार्यान्वयन में सुसंगतता और पारदर्शिता सुनिश्चित हुई।

प्रतिभागियों को मानकीकृत पद्धतियों, डेटा शुद्धता आवश्यकताओं और उत्सर्जन रिपोर्टिंग व सत्यापन के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं से अवगत कराया गया। प्रशिक्षण ने कार्बन बाजारों में विश्वसनीयता, पारदर्शिता और पर्यावरणीय अखंडता सुनिश्चित करने में सुदृढ़ MRV ढांचों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाकर और MRV दिशानिर्देशों की सामान्य समझ को बढ़ावा देकर, यह पहल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन का समर्थन करने और भारत के कार्बन बाजार तंत्र को उसकी जलवायु व सतत प्रतिबद्धताओं के अनुरूप सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है।

मुख्य समाचार झलकियाँ (मई, 2026)

स्वच्छता पखवाड़ा 2026 : जागरूकता एवं जनभागीदारी के माध्यम से स्वच्छता का संदेश



स्वच्छता पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत आयोजित स्वच्छता अभियान में भाग लेते हुए बीईई के अधिकारी एवं कर्मचारी*

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने 16-31 मई, 2026 तक स्वच्छता, पर्यावरणीय सततता और जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों की एक श्रृंखला के माध्यम से स्वच्छता पखवाड़ा 2026 मनाया। इस पखवाड़े भर चलने वाले अभियान में अधिकारियों और कर्मचारियों की उत्साही सहभागिता देखी गई तथा इसकी पहुँच शैक्षणिक व स्वास्थ्य सेवा संस्थानों तक भी बढ़ाई गई, जो एक स्वच्छ, हरित और सतत भारत के दृष्टिकोण के प्रति बीईई की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है।

यह आयोजन संगठन के भीतर जागरूकता-निर्माण पहलों के साथ प्रारंभ हुआ। 19 मई, 2026 को, बीईई ने एक स्वच्छता स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रभावशाली संदेशों के माध्यम से स्वच्छता के महत्व को रचनात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके पश्चात 20 मई, 2026 को स्वच्छता निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें प्रतिभागियों ने स्वच्छता, हाइजीन, पर्यावरण संरक्षण और सतत जीवन पर अपने विचार साझा किए।



निबंध लेखन प्रतियोगिता के दौरान प्रतिभागी अपने विचार साझा करते हुए।

अपनी सामुदायिक पहुँच गतिविधियों के भाग के रूप में, बीईई ने अपशिष्ट पृथक्करण और जिम्मेदार अपशिष्ट निपटान प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए एक इस्टबिन वितरण अभियान चलाया। गवर्नमेंट को-एड सीनियर सेकेंडरी स्कूल और एमसीडी प्राइमरी को-एड स्कूल, सेक्टर 3, आर.के. पुरम, नई दिल्ली, साथ ही FMQ BSF अस्पताल-1 और CGHS मातृत्व एवं स्त्री रोग अस्पताल, आर.के. पुरम में स्वच्छता अवसंरचना को सुदृढ़ करने और स्वच्छ अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को प्रोत्साहित करने हेतु अपशिष्ट-पृथक्करण इस्टबिन वितरित किए गए।



उत्तरदायी अपशिष्ट प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए कचरा पृथक्करण डिब्बों का वितरण करते हुए बीईई के अधिकारी।

बीईई ने एक वृक्षारोपण अभियान भी आयोजित किया, जिसके दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों ने पौधे लगाए और पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाई। कार्यालय परिसर में एक श्रमदान कार्यक्रम ने स्वच्छ और स्वस्थ परिवेश बनाए रखने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व को और रेखांकित किया। यह आयोजन बीईई अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल करते हुए एक वॉकथॉन के साथ संपन्न हुआ, जिसका उद्देश्य स्वच्छता और सतत जीवनशैली के बारे में जागरूकता फैलाना था।

इन पहलों के माध्यम से, बीईई ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने में कर्मचारियों और व्यापक समुदाय दोनों को सफलतापूर्वक शामिल किया, जो स्वच्छ भारत मिशन के उद्देश्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है।



हरित भविष्य के लिए आयोजित वृक्षारोपण अभियान में भाग लेते हुए बीईई के अधिकारी।

ऊर्जा दक्ष मोटर्स और उन्नत इंडक्शन कुकिंग प्रौद्योगिकियों पर हितधारकों के साथ विचार-विमर्श



बीईई द्वारा आयोजित आईई2 से आईई3 इंडक्शन मोटर्स पर हितधारक परामर्श के दौरान प्रतिभागी

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने नई दिल्ली में IE2 से IE3 तीन-चरण इंडक्शन मोटर्स में परिवर्तन पर एक हितधारक परामर्श आयोजित किया, जो औद्योगिक ऊर्जा खपत और उत्सर्जन को कम करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल है। तीन-चरण इंडक्शन मोटर्स लगभग 70 प्रतिशत औद्योगिक बिजली खपत के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे बेहतर मोटर दक्षता भारत के ऊर्जा परिवर्तन का एक प्रमुख घटक बन जाती है।

इस परामर्श का नेतृत्व श्री कृष्ण चंद्र पाणिग्राही, महानिदेशक, बीईई ने श्री कामरान शेख, निदेशक, बीईई और डॉ. अभिषेक शर्मा, निदेशक, बीईई के साथ

मिलकर किया। इसमें एमएसएमई निर्माता, उद्योग संघ, हितधारक और CLASP के प्रतिनिधि एक साथ आए।

चर्चाएँ उद्योग की तत्परता, परीक्षण अवसंरचना, प्रमाणन समय-सीमा और उच्च-दक्षता मोटर्स की ओर एक सुचारु परिवर्तन के लिए आवश्यक सहायता तंत्रों पर केंद्रित रहीं। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए, महानिदेशक ने सभी क्षेत्रों में मोटर्स की महत्वपूर्ण भूमिका और भारत की पीक बिजली मांग को कम करने में उनके संभावित योगदान को रेखांकित किया।

बीईई प्रतिनिधिमंडल ने उन्नत इंडक्शन कुकिंग प्रौद्योगिकियों के एक लाइव प्रदर्शन का भी भ्रमण किया, जिसमें उनकी दक्षता और प्रदर्शन को प्रदर्शित किया गया। निर्माताओं के साथ बातचीत ने सप्लाई-चेन चुनौतियों और भारत व अन्य उभरते बाजारों में अपनाने को बढ़ाने के अवसरों के बारे में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की।

यह सहभागिता ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में तेजी लाने और एक सतत व निम्न-कार्बन भविष्य की ओर भारत के परिवर्तन का समर्थन करने के लिए बीईई के निरंतर प्रयासों को दर्शाती है।

एडीटी (ADEETIE) के अंतर्गत वित्त तक पहुँच सुदृढ़ करने पर आयोजित कार्यशाला के दौरान प्रतिभागी



एडीटी (ADEETIE) योजना के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं के लिए वित्त तक पहुँच सुदृढ़ करने पर विशेषज्ञों द्वारा विचार-विमर्श

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने ADEETIE के अंतर्गत वित्त तक पहुँच को सुदृढ़ करने और वित्तीय संस्थानों की भूमिका को मान्यता देने पर एक कार्यशाला आयोजित की, जिसमें वित्तीय संस्थानों, उद्योग संघों और अन्य प्रमुख हितधारकों के प्रतिनिधियों को एमएसएमई के लिए ऊर्जा दक्षता वित्तपोषण बढ़ाने के मार्गों पर चर्चा करने हेतु एक साथ लाया गया।

इस कार्यशाला ने ADEETIE योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तपोषण अवसरों पर विचार-विमर्श करने और ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने के लिए पूंजी तक पहुँच में सुधार के तंत्र तलाशने हेतु एक मंच के रूप में कार्य किया। प्रतिभागियों ने एमएसएमई के लिए उपलब्ध विभिन्न वित्तीय सहायता प्रणालियों पर चर्चा की और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश की बाधाओं को दूर करने पर अपने विचार साझा किए।

चर्चाओं ने ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों की तैनाती में तेजी लाने और भारत के व्यापक ऊर्जा परिवर्तन उद्देश्यों का समर्थन करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। इस आयोजन ने सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने में नीति-निर्माताओं, उद्योग हितधारकों और वित्तीय संस्थानों के बीच सहयोग के महत्व की पुष्टि की।

यह कार्यशाला वित्त तक पहुँच को सुगम बनाने और एक अधिक प्रतिस्पर्धी, सतत व ऊर्जा-कुशल एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए बीईई की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

रायपुर में स्टील री-रोलिंग क्लस्टर हेतु ADEETIE कार्यशाला



कार्यशाला में भाग लेते हुए एमएसएमई, वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा लेखा परीक्षकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधि।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 7 मई, 2026 को रायपुर में स्टील री-रोलिंग क्लस्टर के लिए एक ADEETIE कार्यशाला आयोजित की।

इस कार्यशाला में एमएसएमई, वित्तीय संस्थानों, ऊर्जा लेखा परीक्षकों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और उद्योग

प्रतिनिधियों सहित 60 से अधिक हितधारकों की सहभागिता देखी गई। यह स्टील री-रोलिंग उद्योग में ऊर्जा-कुशल प्रथाओं को आगे बढ़ाने में शामिल हितधारकों के बीच ज्ञान साझाकरण और सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया।

चर्चाएँ ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने, ADEETIE योजना के अंतर्गत उपलब्ध वित्तपोषण अवसरों और ऊर्जा दक्षता निवेशों तक पहुँच में सुधार की रणनीतियों पर केंद्रित रहीं। प्रतिभागियों ने प्रौद्योगिकी अपनाने में तेजी लाने और क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सहयोग के मार्ग भी तलाशे।

इस कार्यशाला ने अपनी ऊर्जा परिवर्तन यात्रा में एमएसएमई का समर्थन करने के लिए बीईई की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की और एक अधिक सतत व ऊर्जा-कुशल स्टील उद्योग के निर्माण में हितधारक साझेदारियों के महत्व को रेखांकित किया।

आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों की ऊर्जा मांग संबंधी रिपोर्टें जारी



बीईई की आवासीय एवं वाणिज्यिक भवनों की ऊर्जा मांग संबंधी रिपोर्टों का लोकार्पण करते हुए अधिकारीगण।

7 मई, 2026 को, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने भारत के आवासीय और वाणिज्यिक भवन क्षेत्रों में ऊर्जा मांग पर दो महत्वपूर्ण रिपोर्टें लॉन्च कीं, जिनका उद्देश्य ऊर्जा योजना, मांग पूर्वानुमान और लक्षित ऊर्जा दक्षता हस्तक्षेपों का समर्थन करना है।

तीव्र शहरीकरण, बढ़ती आय, बढ़ते उपकरण स्वामित्व और बढ़ती कूलिंग आवश्यकताओं के ऊर्जा मांग पर प्रभाव को पहचानते हुए, बीईई ने मांग-पक्ष ऊर्जा खपत पैटर्न की समझ को सुदृढ़ करने के लिए विस्तृत अध्ययन किए।

CLASP के सहयोग से तैयार रेजिडेंशियल सर्वे रिपोर्ट, विविध भौगोलिक क्षेत्रों और सामाजिक-आर्थिक समूहों को कवर करने वाले एक बड़े पैमाने के हाउसहोल्ड सर्वे के निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। यह अध्ययन घरेलू ऊर्जा खपत पैटर्न और उपकरण स्वामित्व रुझानों में मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

GIZ के साथ विकसित कमर्शियल सर्वे रिपोर्ट, प्रमुख शहरी केंद्रों में वाणिज्यिक भवनों में कूलिंग और बिजली मांग का आँकलन करती है और क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता में सुधार के लिए भविष्य के मांग रुझानों व अवसरों की पहचान करती है।

बीईई की एनर्जी डेटा मैनेजमेंट यूनिट (EDMU) के अंतर्गत विकसित, दोनों रिपोर्टों से नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं और उद्योग हितधारकों के लिए मूल्यवान संसाधन के रूप में काम करने की अपेक्षा है। लॉन्च के दौरान बोलते हुए, महानिदेशक, बीईई, श्री कृष्ण चंद्र पाणिग्राही ने भारत के सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाते हुए ऊर्जा मांग को कम करने और उपभोक्ता लागत को कम करने में ऊर्जा दक्षता के महत्व पर बल दिया।

कानपुर लेदर क्लस्टर के लिए ADEETIE हितधारक संवाद कार्यशाला



कार्यशाला के प्रतिभागियों एवं अधिकारियों का सामूहिक छायाचित्र।

इस कार्यशाला ने लेदर सेक्टर में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के अवसरों को तलाशने के लिए एमएसएमई, उद्योग प्रतिनिधियों, वित्तीय संस्थानों, प्रौद्योगिकी प्रदाताओं और अन्य हितधारकों को एक साथ लाया। कार्यक्रम का केंद्र बिंदु ADEETIE योजना के बारे में जागरूकता पैदा करना और एमएसएमई के लिए इसके लाभों को रेखांकित करना था।

प्रतिभागियों ने उत्पादकता में सुधार, ऊर्जा लागत कम करने और लेदर उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को सुदृढ़ करने के लिए ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर चर्चा की। इस बातचीत ने वित्त तक पहुँच को सुगम बनाने और ऊर्जा दक्षता परियोजनाओं में निवेश की बाधाओं को दूर करने के मार्गों की भी खोज की।

यह कार्यशाला हितधारक सहभागिता और ज्ञान विनिमय के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है, जो ऊर्जा दक्षता के माध्यम से सतत औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के प्रति बीईई की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करती है। ऐसी क्लस्टर-केंद्रित पहलों के माध्यम से, बीईई स्वच्छ और अधिक कुशल प्रौद्योगिकियों को अपनाने में एमएसएमई का समर्थन करना जारी रखता है, जिससे एक अधिक लचीले और सतत औद्योगिक तंत्र में योगदान मिलता है।



मुख्य समाचार झलकियाँ (जून, 2026)

ब्रिक्स साइड इवेंट के रूप में 'विद्युत उपकरणों के मानकों को उन्नत बनाने' विषय पर आयोजित कार्यक्रम



'विद्युत उपकरणों के मानकों को उन्नत बनाने' विषय पर आयोजित ब्रिक्स साइड इवेंट के प्रतिभागियों का सामूहिक छायाचित्र।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल (SEforALL) के सहयोग से, BRICS ऊर्जा मंत्रिस्तरीय प्रक्रिया के भाग के रूप में 24 जून, 2026 को "विद्युत उपकरण मानकों को बढ़ाना" शीर्षक से एक उच्च-स्तरीय साइड इवेंट का आयोजन किया। यह आयोजन BRICS वरिष्ठ ऊर्जा अधिकारियों की समिति की चौथी बैठक और BRICS ऊर्जा मंत्रियों की 11वीं बैठक के साथ आयोजित किया गया, जिसमें BRICS देशों के नीति-निर्माताओं, उद्योग नेताओं, निर्यातकों, वित्तीय विशेषज्ञों और ऊर्जा दक्षता हितधारकों को एक साथ लाया गया।

इस आयोजन ने उन्नत विद्युत उपकरण मानकों के माध्यम से ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाने और BRICS सदस्य देशों के बीच सहयोग को सुदृढ़ करने पर विचार-विमर्श करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य किया। चर्चाओं ने स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को तेज करने में सामंजस्यपूर्ण मानकों, तकनीकी नवाचार और सहयोगात्मक वित्तपोषण दृष्टिकोणों के महत्व को रेखांकित किया।

रेफ्रिजरेशन एंड एयर-कंडीशनिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (RAMA), कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लायंसेज मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन (CEAMA), एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL), BSES दिल्ली, CLASP तथा वोल्टास, बॉश, अटलस कोप्को, डाइकिन इंडिया, IFB, हायर, व्हर्लपूल, सैमसंग, बजाज इलेक्ट्रिकल्स और डेलॉइट सहित प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुतियां व वक्तव्य दिए। वित्त पेशेवरों और सेक्टर विशेषज्ञों ने भी ऊर्जा-कुशल प्रौद्योगिकियों में निवेश को सक्षम बनाने पर अपने विचार साझा किए।

मुख्य चर्चा BRICS देशों में विद्युत उपकरण मानकों को सामंजस्यपूर्ण बनाने, वास्तविक समय ऊर्जा अनुकूलन के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-सक्षम समाधानों का लाभ उठाने तथा उच्च-दक्षता उपकरणों की व्यापक तैनाती को सुगम बनाने के लिए सुदृढ़ वित्तपोषण तंत्र विकसित करने पर केंद्रित रही। प्रतिभागियों ने संरेखित नियामक ढांचों, बेहतर तकनीकी सहयोग और नवीन वित्तीय मॉडलों की आवश्यकता पर बल दिया।

इस साइड इवेंट ने बाजार परिवर्तन को आगे बढ़ाने, ऊर्जा लचीलेपन को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने में सामूहिक कार्रवाई के महत्व को रेखांकित किया। इसने ऊर्जा दक्षता को आगे बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और एक सतत व निम्न-कार्बन ऊर्जा भविष्य का समर्थन करने के प्रति BRICS देशों की प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

बीईई ने ऊर्जा-कुशल भवनों और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन के लिए तमिलनाडु के साथ सहयोग सुदृढ़ किया



बीईई प्रतिनिधिमंडल की ऊर्जा-कुशल भवनों और औद्योगिक डीकार्बोनाइजेशन पर तमिलनाडु के अधिकारियों के साथ चर्चा के दौरान।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल, जिसमें श्रीमती पी. सामल, निदेशक; श्री श्याम सुंदर, निदेशक; और श्री सुनील खंडारे, निदेशक शामिल थे, ने ऊर्जा-कुशल भवनों और औद्योगिक ऊर्जा परिवर्तन पहलों पर चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए तमिलनाडु का भ्रमण किया।

प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्यिक भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण सतत भवन संहिता (ECSBC) और आवासीय भवनों के लिए इको निवास संहिता (ENS) के कार्यान्वयन पर चेन्नई मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (CMDA) और तमिलनाडु पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (TNPDC) के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की।

विचार-विमर्श प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीतियों और राज्य भर में इसे अपनाने को बढ़ाने पर केंद्रित रहा।

बीईई टीम ने TNSDA इनोवेशन डिस्प्ले का भी भ्रमण किया, जहाँ उन्होंने राज्य नामित एजेंसी के रूप में TNPDC के CMD, श्री जे. राधाकृष्णन, IAS के नेतृत्व में ऊर्जा दक्षता में तमिलनाडु की पहलों और उपलब्धियों की समीक्षा की।

इस भ्रमण का समापन ऊर्जा सचिव, तमिलनाडु सरकार, तथा CMDA और TNPDC के अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय बैठक में हुआ, जिसमें ECSBC और ENS को राज्य-व्यापी स्तर पर अपनाने के लिए नीति ढांचे और कार्यान्वयन रोडमैप पर चर्चा की गई। इस बैठक ने सतत, ऊर्जा-कुशल भवनों को बढ़ावा देने और निम्न-कार्बन निर्मित परिवेश की ओर परिवर्तन में तेजी लाने के प्रति दोनों संस्थानों की साझा प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि की।

भ्रमण के दौरान, श्री पी. श्याम सुंदर ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी (ऊर्जा) श्री अनिल मेश्राम और अतिरिक्त मुख्य सचिव (एमएसएमडी) डॉ. अतुल आनंद को भी ADEETIE योजना के बारे में जानकारी दी, जिसमें तमिलनाडु में पहचाने गए औद्योगिक क्लस्टरों में निवेश को अनलॉक करने, औद्योगिक ऊर्जा दक्षता में सुधार करने और सतत आर्थिक विकास का समर्थन करने की इसकी क्षमता को रेखांकित किया गया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के उपलक्ष्य में आयोजित योग सत्र



अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 पर विशेष योग सत्र में भाग लेते बीईई अधिकारी और कर्मचारी।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE) ने 19 जून, 2026 को अपने कार्यालय परिसर में एक विशेष योग सत्र आयोजित किया। इस सत्र में बीईई अधिकारियों और कर्मचारियों

की उत्साहपूर्ण सहभागिता देखी गई।

इस पहल का उद्देश्य शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक शांति और समग्र कल्याण को बढ़ाने के एक प्रभावी माध्यम के रूप में योग को बढ़ावा देना था। प्रतिभागियों ने विभिन्न योग आसनों, श्वास अभ्यासों और ध्यान तकनीकों में भाग लिया, जिन्होंने एक स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली अपनाने के महत्व पर बल दिया।

इस सत्र ने तनाव को कम करने, फिटनेस में सुधार और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में योग की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई। इसने एक स्वस्थ कार्यस्थल संस्कृति को प्रोत्साहित करने और कर्मचारियों को अधिक संतुलित व उत्पादक जीवन के लिए अपनी दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने हेतु प्रेरित करने के प्रति बीईई की प्रतिबद्धता को भी दर्शाया।

ईसीएसबीसी मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम का आयोजन



ईसीएसबीसी मास्टर ट्रेनर कार्यक्रम के चार बैचों के प्रशिक्षण सत्रों के दौरान प्रतिभागी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE), विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) के सहयोग से, जून, 2026 के दौरान TERI ग्राम, गुरुग्राम में ECSBC मास्टर ट्रेनर प्रोग्राम के चार बैचों का सफलतापूर्वक संचालन किया। इस पहल का उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण एवं सतत भवन संहिता (ECSBC) 2024 और इको निवास संहिता (ENS) 2024 के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय क्षमता को सुदृढ़ करना है, जिससे भारत में ऊर्जा-कुशल और सतत भवनों की ओर परिवर्तन में तेजी आएगी।

8-12 जून, 2026 को आयोजित पहला बैच, TERI रिट्रीट सेंटर में शुरू किया गया और इसमें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, ऊर्जा प्रबंधक, सततता पेशेवर, सरकारी अधिकारी, शोधकर्ता, शिक्षाविद और मौजूदा ECSBC मास्टर ट्रेनर एक साथ आए। उद्घाटन सत्र में TERI के सीनियर डायरेक्टर श्री संजय सेठ; निदेशक, बीईई श्रीमती पी. सामल; और महानिदेशक, बीईई श्री कृष्ण चंद्र पाणिग्राही की टिप्पणियां शामिल थीं, जिन्होंने भारत की ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु प्रतिबद्धताओं और सतत विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने में ऊर्जा-कुशल भवनों की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

उद्घाटन बैच की गति को आगे बढ़ाते हुए, बाद के बैच 16 जून, 22 जून और 29 जून, 2026 को TERI ग्राम, गुरुग्राम में शुरू हुए। इन कार्यक्रमों में देशभर से आर्किटेक्ट, सलाहकार, सरकारी अधिकारी, शिक्षाविद और भवन क्षेत्र के पेशेवरों की सहभागिता आकर्षित हुई, जो जलवायु-अनुकूल विकास को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

पांच दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम तकनीकी सत्रों, सिमुलेशन अभ्यासों, इंटरैक्टिव चर्चाओं और व्यावहारिक केस स्टडीज को जोड़ता है, जो प्रतिभागियों को ECSBC 2024 और ENS 2024 का व्यावहारिक अनुभव प्रदान करता है। शामिल मुख्य विषयों में जलवायु-अनुकूल डिजाइन, सतत साइट योजना, बिल्डिंग एनवलप परफॉर्मेंस, ऊर्जा-कुशल लाइटिंग व विद्युत प्रणालियां, उच्च-प्रदर्शन HVAC प्रौद्योगिकियां, जल संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण, बिल्डिंग एनर्जी सिमुलेशन और अनुपालन मार्ग शामिल हैं।

सफल समापन पर, प्रतिभागियों को ECSBC मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रमाणित किया जाता है, जो सतत भवन प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने और कार्यान्वित करने में सक्षम विशेषज्ञों के एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क के निर्माण में योगदान देता है। यह कार्यक्रम भारत के निम्न-कार्बन, संसाधन-कुशल और ऊर्जा-सुरक्षित निर्मित परिवेश के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समाचारों की सुखियों में ई-कुकिंग

The Hindu Bureau
NEW DELHI

A photograph of a woman with dark hair, wearing a green sari with a gold border, standing in a kitchen. She is holding a black spatula and stirring food in a pan on a gas stove. The kitchen has pink tiled walls.

The Hindu earlier reported induction stove and microwave oven sales spiked as much as 50% since the government flagged supply concerns over LPG on Iran-U.S. nuclear war.

Preferred on



VAJIRAM & RAVI
Institute for IAS Examination

Fostering Innovation Micro-Entrepreneurs India Clean Cooking

India's micro food economy sits at the intersection of livelihoods, energy, and informality. With an estimated five million micro-food enterprises operating across the country, these vendors feed millions every day while working on thin margins, long hours, and high exposure to heat, smoke, and fuel price volatility. Despite near-universal electrification at the household level, cooking for these enterprises has remained dominated by LPG and in some cases, traditional fuels such as firewood and coal. The latest field evidence from a research programme, funded by Shell Foundation via the Transforming Energy Access platform and executed by the Energy Foundation, offers a different picture: electric cooking and associated by-product thermal options for this segment hold a no longer a niche pathway when vendors devices, infrastructure, and support systems align with

2. _____

Levi updated on 18 April, 2024 · 8 min read

disruptions, inductive coolings could add ~27 GW to power demand



By WASE KHALID, NIHA CHENNA